भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
भारी उद्योग विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4386
जिसका उत्तर गुरुवार, 20 फरवरी 2014 को दिया जाना है

डीजल वाहनों की मांग

4386. श्री अब्दुल रहमान:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान डीजल वाहनों की मांग में भारी वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में डीजल के वाहनों की मांग भारी सब्सिडीयुक्त डीजल की उपलब्धता के कारण है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है एवं सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) सरकार द्वारा देश में डीजल के वाहनों का पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव के कारण डीजल के वाहनों के विनिर्माण को हतोत्साहित करने के लिए क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री
(श्री प्रफुल पटेल)

(क) और (ख): सूचना एकत्रित की जा रही है।

(ग) और (घ): जी, नहीं। डीजल पर सब्सिडी उन कारकों में से केवल एक है जो डीजल कारों को अधिक मितव्ययी बनाता है। अन्य कारक डीजल कारों की उच्च ईंधन क्षमता तथा टार्क तथा सड़क पर उन्नत वाहन नियंत्रण के रूप में बेहतर कार्य निष्पादन हैं।

डीजल वाहन अर्थव्यवस्था में, ईंधन की खपत में कमी लाने, देश की ऊर्जा सुरक्षा में योगदान करने, रोजगार एवं विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

(ङ): डीजल वाहनों के विनिर्माण को विशेष रूप से हतोत्साहित करने की सरकार की कोई योजना नहीं है। तथापि, अनेक कारणों से पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए कई एकीकृत व्यापक प्रयासों की आवश्यकता है। सरकार ने देश में विद्युत वाहनों के विनिर्माण और अंगीकरण में तेजी लाने के लिए एक सामान्य रूपरेखा उपलब्ध कराने हेतु नैशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन योजना 2020 शुरू की है। नैशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन योजना 2020 का मूलभूत उद्देश्य देश की ऊर्जा सुरक्षा में वृद्धि करना और डीजल सहित सभी गैसोलिन आधारित परिवहनों को हटाकर विद्युत एवं हाइब्रिड वाहनों के माध्यम से पर्यावरण पर परिवहन के प्रभाव को कम करना है। पणधारकों के साथ विस्तृत रूप से परामर्श तथा गहन अध्ययन के आधार पर सरकार ने इस पहल को एक मिशन मोड के रूप में शुरू करने का अनुमोदन किया है।

*****